

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय म०प्र०राजस्व मण्डल ग्वालियर  
कैम्प रीवा, जिला रीवा म०प्र०



RS-201-

202  
16.6.15

निगरानी 2194-II-15

रामजतन तनय श्री गोबिन्द राम निवासी ग्राम चौका सोनवर्धा,  
तहसील मउमंज जिला रीवा म०प्र० निगरानीकर्ता  
बनाम

1. रामजी तनय रामनिहोर ब्रा० निवासी ग्राम चौका सोनवर्धा,  
तहसील मउमंज जिला रीवा म०प्र०  
गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिस्व आदेश न्यायालय अपर आयुक्त  
महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र०क्र० 435/निगरानी/  
2005-2006 में पारित आदेश दिनांक 30.3.15  
के बिस्व अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भूरा० संहिता

श्री. 3 महीने की अवधि में  
द्वारा आज दिनांक 16.6.15 के  
प्रस्तुत किया गया

क्रमांक 5852 संक्षिप्त खर्च रीवा  
रजिस्टर्ड फीस आज  
दिनांक प्राप्त  
महोदय,  
न्यायालय ग्वालियर  
राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चौका सोनवर्धा  
की भूमि ख० नं० 57 रकबा 1.06 ए. , 105/20 , 128/44, 150/1 रकबा  
0.32 ए. , 78 रकबा 0.62 ए. कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.64 ए. तहसील  
मउमंज के भूमि के सम्बन्ध में बटनवारा आवेदन विचारण न्यायालय में  
प्रस्तुत किया गया, जिस प्रकरण में आवेदक को सूचना व सुनवायी का  
अवसर नहीं दिया गया, तथा पत्नी सजरा खानदान के आधार पर  
विचारण न्यायालय में बटनवारा नामा० आदेश पारित कर दिया  
गया, जिसकी जानकारी होने पर आवेदक के द्वारा अनु० अधिकारी के  
न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अपील प्र० क्र० 212/अ० 27/98-99  
में अनु० अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 9.6.2000 को आदेश पारित  
हुये अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को  
बिधिवत सुनवायी किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, जिस आदेश


रामन

(65)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2194- दी 115 जिला- रीवा

राजस्व विरुद्ध रामजी वा.

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अनीष श्रीवास्तव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमीशनर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक <u>435/निगा./2005-06</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-3-15</u> के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक <u>16-6-15</u> प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

मे अनुअधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 9.6.2007 का आदेश पारित हुये अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः बिचरण न्यायालय को विधिवत सुनवायी किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, जिस आदेश

समस्त